भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *235
5 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

*235. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
सुश्री बाँसुरी स्वराजः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र को आवंटित कुल बजटीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(ख) उक्त मिशन की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत किस प्रकार की और कितनी प्रायोगिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत, विशेषकर झारखंड में, स्वीकृत प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा और निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाले इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या किसी हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण संबंधी प्रायोगिक परियोजना से उत्पादन शुरू हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2025-27 के बीच उत्सर्जन में कमी के लिए निर्धारित उद्योग-व्यापी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) से (च) : विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन" के संबंध में श्री दिनेशभाई मकवाणा तथा सुश्री बाँसुरी स्वराज संसद सदस्य द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए प्रस्तुत किए गए लोक सभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *235 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): इस्पात मंत्रालय को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 455 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए झारखंड के बोकारो में एक परियोजना सहित 05 प्रायोगिक परियोजनाएं प्रदान की हैं। ये परियोजनाएं वर्टिकल-शॉफ्ट आधारित डीआरआई उत्पादन में प्राकृतिक गैस का हाइड्रोजन के साथ आंशिक प्रतिस्थापन, तथा कोयले एवं कोक की खपत को कम करने के लिए मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन के उपयोग (इंजेक्शन) पर केंद्रित हैं। प्रायोगिक परियोजनाओं के समग्र सेट के पूरा होने की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2029-30 तक है। हालाँकि, झारखंड के बोकारो में क्रियान्वित परियोजना का अक्टूबर, 2026 तक पूरा होना निर्धारित है। ये प्रायोगिक परियोजनाएँ डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के चरण में हैं और इनमें हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। मेकॉन लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई, योजना कार्यान्वयन एजेंसी है और प्रायोगिक परियोजनाओं की नियमित निगरानी करती है। प्रायोगिक परियोजनाओं की आवधिक निगरानी के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति और संचालन समिति का भी गठन किया गया है।

(च): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 23.06.2025 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 405 (अ.) के तहत वर्ष 2025-26 तथा 2026-27 के लिए इस्पात क्षेत्र की बाध्य संस्थाओं हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है। यह अधिसूचना एमओईएफएंडसीसी की वेबसाइट यूआरएल https://moef.gov.in/storage/tender/1750856052.pdf. पर उपलब्ध है।

******